



## स्वच्छ विकास और जलवायु पर एशिया-प्रशांत साझेदारी

### परिचय

स्वच्छ विकास और जलवायु पर एशिया- प्रशांत साझेदारी के तहत एशिया-प्रशांत क्षेत्र के सात बड़े देश - ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, जापान, कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका - एकजुट हुए हैं, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था, जनसंख्या और ऊर्जा इस्तेमाल के आधे से भी अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। बढ़ती ऊर्जा जरूरतों और वायु प्रदूषण, ऊर्जा सुरक्षा व जलवायु परिवर्तन जैसे संबद्ध मुद्दों से निबटने के प्रयास में ये आपस में सहयोग कर रहे हैं।

सरकारी और निजी क्षेत्रों के नए व सामूहिक प्रयास के तौर पर एशिया- प्रशांत साझेदारी का गठन आर्थिक विकास बढ़ाने, निर्धनता घटाने और स्वच्छतर, ज्यादा कुशल तकनीकों के विकास और इनकी तैनाती के उद्देश्य से किया गया है।

यह साझेदारी मौजूदा दोषक्षीय और बहुपक्षीय पहल की बुनियाद को सुदृढ़ बनाते हुए, और क्योटो प्रोटोकॉल का समर्थन करते हुए, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर ढांचागत योगदान को आगे बढ़ाती है।

### साझेदारी के बिंदु

साझेदारी के तहत कार्य योजनाओं के विकास और क्रियान्वयन के लिए आठ सरकारी और निजी कार्य बल गठित किए गए हैं। ये कार्य बल पांच ऊर्जा गहन क्षेत्रों - एल्युमीनियम, निर्माण और उपकरण, सीमेंट, कोयला खनन और इस्पात - तथा ऊर्जा आपूर्ति करने वाले तीन क्षेत्रों - स्वच्छतर जीवाश्म ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और वितरित उत्पादन, और विद्युत उत्पाद व संचरण- पर केंद्रित हैं।

### साझेदारी की गतिविधियां

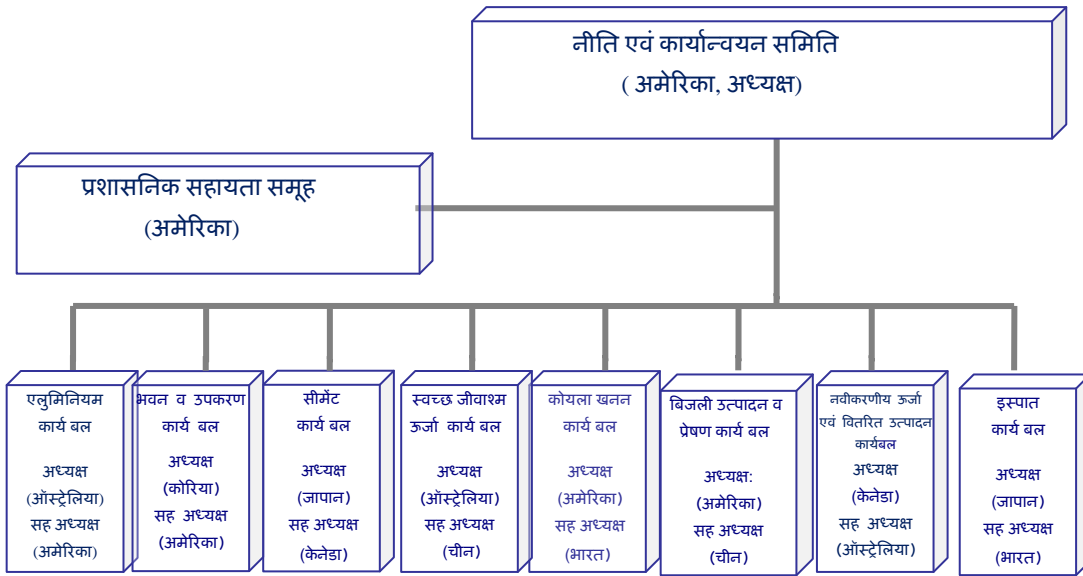
एशिया-प्रशांत साझेदारी के कार्यों में विभिन्न तरह की गतिविधियां शामिल हैं। साझेदारी परियोजनाओं का शुरुआती हिस्सा क्षेत्रीय आकलन, क्षमता निर्माण, बेहतर प्रयोगों की पहचान, और तकनीकी शोध और प्रदर्शन पर जोर देता है।

साझेदारी का कार्य प्रदर्शित करने वाले कुछ उदाहरण हैं:

- \* एल्युमिनियम उत्पादन में बाॅक्साइट अवशिष्ट प्रबंधन।
- \* ऊर्जा कुशल प्रकाश के मानकीकरण में सहयोग।
- \* सीमेंट भट्टियों के कूड़े का ईंधन में रूपांतरण।
- \* कोयला-चालित बिजलीघरों में कार्बन संग्रहण तकनीक में सुधार।
- \* कोयला खदान स्वास्थ्य और सुरक्षा रणनीतियों का विकास।
- \* विद्युत उत्पादन में बेहतर प्रयोगों का आदान-प्रदान।
- \* सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना, और
- \* स्वच्छतर इस्पात तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाना।

### सांगठनिक ढांचा

नीति और कार्यान्वयन समिति (पीआईसी) साझेदारी के काम का निरीक्षण करती है, कार्य बल को दिशा-निर्देश देती है और नियत समय पर उनके काम-काज की समीक्षा करती है। प्रशासनिक सहायता समूह, जिसकी मेजबानी फिलहाल अमेरिका के पास है, व्यापक रूप से पीआईसी और साझेदारी का सहयोग करता है। कार्य बल का नेतृत्व सभापति और उप-सभापति करते हैं, जो सरकारी-निजी क्षेत्र के सहयोग का सर्वेक्षण करते हैं।



## पृष्ठभूमि

एशिया-प्रशांत साझेदारी की घोषणा जुलाई, 2005 में विएन्त्यान, लाओस में 37वें आसियान मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हुई थी। उसके बाद सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में जनवरी, 2006 में मंत्री स्तरीय बैठक के उद्घाटन के अवसर पर इसकी शुरुआत हुई। सिडनी में मौजूद मंत्रिगण एक घोषणापत्र, सरकारी विज्ञप्ति और कार्य योजना पर भी सहमत हुए।

अप्रैल, 2006 में नीति और क्रियान्वयन समिति (पीआईसी) की कार्यबलों के साथ बर्कले, अमेरिका में बैठक हुई। कार्य बलों ने संबंधित क्षेत्रों से जुड़ी प्राथमिकताओं और विकासशील कार्य योजनाओं को चिह्नित करना शुरू किया। अक्टूबर, 2006 में जेजू, कोरिया में पीआईसी की दूसरी बैठक में, साझेदारों ने आठ कार्य योजनाओं को अनुमोदित किया, जिनमें करीब सौ विभिन्न परियोजनाएं और गतिविधियां जुड़ी हुई थीं।

कार्य बलों ने तब से अपने काम काज का कार्यान्वयन चरण शुरू किया और वे लगातार बैठकें करने लगे। जुलाई, 2007 में टोक्यो, जापान में पीआईसी की बैठक में कार्य बलों ने अपने काम की रिपोर्ट दी, और पीआईसी ने नई परियोजनाओं को अनुमोदित किया। अक्टूबर, 2007 में नई दिल्ली में मंत्री स्तरीय बैठक में मंत्रियों ने सातवें साझेदार के तौर पर कनाडा का स्वागत किया, कार्य योजनाओं और इनसे संबंधित 100 से अधिक परियोजनाओं, साथ ही साथ 18 ध्वजपोत परियोजनाओं की पहचान की, और एशिया-प्रशांत ऊर्जा तकनीकी सहयोग केंद्र की शुरुआत की घोषणा की।

मई 2008 में पीआईसी के सदस्यों की सिआटल, अमेरिका में बैठक हुई जहाँ कार्य बलों ने, जो कार्यान्वयन चरण में अब तक काफी आगे बढ़ चुके थे, अपने कार्य की रिपोर्ट पेश की। अक्टूबर 2008 में वैंकूवर कनाडा में हुई पीआईसी की बैठक में एपीपी पणधारियों ने अपने विचार और नज़रिए सामने रखे जबकि पीआईसी ने एक ध्वजपोत योजना सहित नई परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया।

मई 2009 में गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में पीआईसी की बैठक में कार्य बलों ने - जो अपने कार्य सम्पूर्ण करने के लिए बैठकें करते रहते हैं - प्रगति की जानकारी दी और पीआईसी सदस्यों ने एपीपी की भावी दिशा के बारे में विचार विमर्श किया, तथा एक ध्वजपोत योजना सहित और परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया।

साझेदारी, इसकी आनेवाली घटनाओं, और इनसे जुड़ने के बारे में और जानकारी के लिए कृपया [www.asiapacificpartnership.org](http://www.asiapacificpartnership.org) पर देखें या  
Administrative Support Group,  
APP\_ASG@state.gov.  
पर संपर्क करें